

भारत निवासन आवृत्ति

समिति

नई दिल्ली, ८ जून, १९७२

का० आ० १७६(च).—लोक प्रतिनिधित्व अधिकार, १९५१ की घारा २२ की उपघारा  
(१) घारा प्रदत्त गतियों का प्रयोग करते हुए, उषा घंपनी प्रधिसूचना सं० ४३४/मीजो/७२  
(१), तारीख २१ फरवरी, १९७२ की प्रधिकार करते हुए निवासन आयोग निम्नलिखित आफिसरों  
को भीजोरम संबंध राज्यकोष में, भीजोरम (म०ज०आ०) संसदीय निवासन क्षेत्र के रिट्रिविंग आफिसर  
की उसके हुत्यों के पासन में सहायता करने के लिए, एतद्वारा निमुक्त करता है :

- १ भपर उपायुक्त, विद्या भीजो, एजल।
- २ उपर्युक्त घाफिसर, लूगलेह।
- ३ उपर्युक्त घाफिसर, पारी खास्टेट, उपर्युक्त लौहा।

[सं० ४३४/मीजो/७२ (१)]

आदेश से,

१० ग्र० राजगोपालन, सचिव।

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

ग्रासाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १३३] नई विल्सनी, मनमवार, भार्व ७, १९७२/फाल्गुन १७, १८९३

No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 1972/PHALGUNA 17, 1893

इस भाग में विशेष रूठ संलया ही आती है जिससे कि यह भाजग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

### MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

#### ORDER

New Delhi, the 7th March, 1972

S.O. 177(E)/18/IDRA/72(5).—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. India Machinery Company Limited, Howrah, is engaged in the Scheduled Industries, namely, Industrial instruments, machine tools etc.

And whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

Shri A. Bose, Special Officer & Ex-officio Secretary, to the Government of West Bengal, Department of Commerce and Industries, Calcutta

*Members*

Shri H. K. Paul Deputy Manager Industrial Reconstruction Corporation of India, Calcutta.

Shri S. C. Banerjee, Industrial Advisor Directorate General of Technical Development New Delhi.

2. The above body shall submit its report within a period of six weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. 25(26)/72-PEC.]

K. S. BHATNAGAR, Lt Secy

ग्रौद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 7 मार्च, 1972

का० आ० 177(प्र) 15/आई० ई० प्रार० ए० 72(5).—यत मैसर्स इण्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक ग्रौद्योगिक उपकरण अनुसूचित उद्योग अर्थात् ग्रौद्योगिक उपकरण, मशीनी औजार आदि के उद्योग में लगा है,

और यतः केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि उक्त ग्रौद्योगिक उपकरण में विनियमित वस्तुओं से सम्बन्धित उत्पादन के परिमाण में भारी कमी आ गई है। जिसके लिए वर्तमान ग्राहिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई ग्रौविध्य नहीं है।

यतः ग्रब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की व्यापारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस मामले की परिस्थितियों का पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एन्डडारा एक निकाय नियमन करती है जिस में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

ग्राहक ---

श्री ए० बोस,

विशेष अधिकारी एवं पदेन सचिव

विणियमन और उद्योग विभाग,

पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता।

मदस्य ---

ध्रो ए० ब० के० नाल,

उप्र प्रबन्धक,

भारतीय ग्रौद्योगिक पुनर्गठन निगम,

कलकत्ता।

श्री एस० सी० बनर्जी,  
 श्रीद्योगिक सलाहकार  
 तकनीकी विकास महानिदेशालय,  
 नई दिल्ली ।

2. उपरोक्त निकाय राजपत्र में इम आदेश के प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह की अवधि  
 के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा ।

[म० पा० 25(26)/72-पी० ई० मी०]

के० एस० भट्टाचार, मन्त्रकुल मंत्री ।

